सरकार का भगीरथ प्रयास, सूखे 1931 झरनों में बहने लगी जलधार

जितेंद्र शर्मा • जागरण

- भारतीय हिमालयी क्षेत्र के आधे से अधिक बारहमासी झरनों के सूखने पर नीति आयोग ने जताई थी चिंता
- मिशन मोड पर स्प्रिंगशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा भूमि संसाधन विभाग, 15 राज्यों में चल रहा काम

नई दिल्ली : भारतीय हिमालयी क्षेत्र व अन्य पर्वत शृंखलाओं के आसपास करीब 20 करोड़ आबादी झरनों के पानी पर निर्भर है, लेकिन कई दशकों तक इनके रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके परिणामों पर 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट ने चेताया कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के आधे से अधिक बारहमासी झरने सूख चुके हैं या फिर मौसमी हो गए हैं। तब आयोग की ही सिफारिश पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने स्प्रिंगशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। 15 राज्यों के 4,327 झरनों को चिह्नित कर भू विज्ञानियों की टीमें लगाई गईं। सरकार का दावा है कि 28 फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 1931 झरने पुनर्जीवित हो चुके हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में लगभग 50 लाख झरने हैं। करीब 30 लाख झरने सिर्फ हिमालयी क्षेत्र में हैं। यह बारहमासी झरने ही वहां की आबादी के लिए जल का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन बदलते पर्यावरण व वर्षा क्रम, भूकंपीय गतिविधियों, भू-उपयोग परिवर्तन आदि का प्रभाव झरनों पर पड़ा। इस कारण आधे से अधिक बारहमासी झरने सूख गए या सूखने की स्थिति में पहुंच गए।

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितिन खाड़े ने बताया कि झरनों को पुनर्जीवित करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इनके जल स्रोत को खोजना आसान नहीं होता। ऐसे में भूमि संसाधन विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत स्प्रिंगशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। हाइड्रोजियोलाजिस्ट से प्रशिक्षण दिलाकर पैरा-हाइड्रोजियोलाजिस्ट की टीमें तैयार की गईं। उन्होंने बताया कि झरनों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया में छह चरण होते हैं। सबसे पहले झरनों और उनके जल स्रोतों की मैपिंग कराई जाती है। दूसरा क्रम वहां डाटा मानीटरिंग सिस्टम लगाने का होता है। इसके बाद संबंधित भौगोलिक क्षेत्र पर झरने के सामाजिक पहलू की रिपोर्ट तैयार की जाती है। चौथे क्रम में हाइड्रोलाजिकल मैपिंग व लेआउट निर्माण कर री-चार्ज एरिया चिह्नित किया जाता है। पांचवां क्रम जल स्रोत प्रबंधन के ढांचे के निर्माण का होता है। अंत में झरने के पुनर्जीवन की गतिविधियों की सतत निगरानी होती है। संयुक्त सचिव ने बताया कि कार्यक्रम के परिणामों को इन दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। हिमाचल के बेहा गांव में झरने का डिस्चार्ज वाल्यूम 71.49 प्रतिशत बढ़ चुका है। इसी तरह मेघालय के ईस्ट गारो जिले के पलवांग झरने के जल प्रवाह में 99.93 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है।

राज्य	चिह्नित झरने	पुनर्जीवित झरने
अरुणाचल प्रदेश	25	09
असम	36	33
गोवा	75	00
हिमाचल प्रदेश	415	127
जम्मू-कश्मीर	690	334
झारखंड	64	34
लद्दाख	13	07
मणिपुर	155	00
मेघालय	331	272
मिजोरम	1465	598
नगालैंड	171	85
ओड़िशा	78	72
सिक्किम	78	40
तमिलनाडु	26	डाटा का उल्लेख नहीं
उत्तराखंड	705	320
कुल	4327	1931

हिमालय में पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करने के लिए हरित भारत मिशन शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने हरित भारत के लिए मंगलवार को एक अद्यतन राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट, हिमालय व अरावली पर्वत शृंखला में क्षीण हो चुके वन पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना है। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा उन्मूलन दिवस पर जारी दस्तावेज में उत्तर-पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों को हरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मिशन का उद्देश्य 100 लाख हेक्टेयर भूमि में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, वन आश्रित परिवारों की आय में वृद्धि करना है।

nwda.gov.in